(iv) farmers training centres and other programmes of farmers training. This feedback is systematically analysed in the research stations and agricultural universities and the research programmes re-oriented as per need.

निराश्रित तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिये सामाजिक बीमा योजना

1805. **श्री उग्रसेन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निराश्रित और वृद्ध व्यक्तियों की बड़ी संख्या पूर्णतया उपेक्षित है ; और

(ख) क्या सरकार उनके लिए कोई सामाजिक बीमा योजना लागू करने पर बिचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर)

(क) भारत की 1971 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष या इस से ऊपर की आयु के व्यक्तियों की कुल संख्या 261.41 लाख थी ।

निराश्रित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । राष्ट्रीय स्तर पर इन आंकड़ो को इकटठा करने में परिभाषा, प्रचालन औचित्य, लागत, जनशक्ति आदि की विकट समस्याएं आती हैं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shortage of Fertilisers

1806. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there has been a shortage of certain varieties of fertilisers in the country and their market price is considerably higher than that of other varieties; and

(b) if so, the reasons therefor and steps Government propose to take in respect thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). Adequate quantities of fertilisers are available in the country to meet the requirements of the farmers for all major nutrients, namely, nitrogen, phosphate and potash. In view of differing agronomic properties, differing costs of production and differing farmers preferences, it is not possible to compare the prices of different varieties of fertilisers. However, care is taken to see that farmer is not made to pay excessive price just because he has a preference for a particular product.

Executive Engineers in C.P.W.D. officiating in the Grade for more than 20 Years

1807. SHRI G. M. BANATWALA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state number of Executive Engineers C.E.S. Class I and C.E.E.S. Class I (Electrical) in C.P.W.D. who are officiating for more than 15 years but less than 20 years and more than 10 years but less than 15 years in that grade and for more than 20 years as on the 1st April, 1977 separately for Civil and Electrical?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): Appointment to the grade of

Executive Engineers is made from two sources viz. Assistant Executive Engineers and Assistant Engineers. For recruitment through the two sources a quota has been fixed by rule, statutorily. However, due to non-availability of people from one source, the posts have been, in the exigencies of public service, filled by appointment of the people from the other group. The Supreme Court has held that such people having been appointed in excess of their quota, will have to be pushed down and absorbed in the year in which they can be adjusted against their own quota vacancies. Their officiating appointment on a regular basis, will therefore, be deemed to have commenced only from the date of their absorption against their quota. Due to this there will be a difference between the date of appointment, in exigencies of public service, in excess of their quota and officiating appointment on a regular basis. Both these information are furnished hereunder:—

	Civil Engineers		Electrical Engineers	
	On regular basis	Total (including regular and ad-hoc)	Regular	Total (including regular and ad-hoc)
No. of EEs Officiating for more than 20 years .	..	7	..	
No. of EEs officiating between 15 and 20 years	3	52	..	4
No. of EEs. officiating between 10 and 15 years .	17	57	41	16

कृषि उत्पादों की लेवी वसूली के लिये भुगतान की अवधि सीमा

1808. श्री मीठा लाल पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में लेवी के तरीके से चावल तथा अन्य उत्पादों की वसूली के कारण देय राशि के भुगतान के लिये कोई अवधि सीमा निश्चित की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विलम्ब से किये गये भुगतान पर भी कोई ब्याज देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अन्य लेवी वसूली राज्यों में इस बारे में क्या नीति अपनाई गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग). क्योंकि भुगतान शीघ्र किए जाते हैं इसलिए ब्याज देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है । राजस्थान में लेवी चावल का शीघ्र और सामयिक भुगतान करने के लिये भाण्डागार रसीद तौल जांच-मेमो के प्रस्तुत करने पर 90 प्रतिशत भुगतान किया जाता है और किस्म सबंधी कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद जिला प्रयोगशाला से किस्म संबंधी सर्टिफिकेट प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है । अन्य राज्यों, जहां पर भारतीय खादय निगम केन्द्रीय भंडार के लिए सीधे मिल मालिकों से चावल की वसूली कर रहा है, के मामले में भी ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में 'सलेक्शन ग्रेड'

1809. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :